गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 076
दि. 15.07.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मानसून सत्र में सुधारों का मेगा एजेंडा, संसद में कई अहम विधेयकों पर होगी निर्णायक बहस

नई दिल्ली। संसद का आगामी मानसून सत्र राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार इस सत्र में ऐसे कई बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनका असर केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, कॉर्पोरेट क्षेत्र, चुनावी ढांचे और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा। सरकार का फोकस एक ओर आर्थिक सुधारों को नई गति देने पर रहेगा तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार-रोधी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, उच्च शिक्षा में बदलाव तथा चुनावी संरचना से जुड़े संवेदनशील विषयों पर भी पहल की जा सकती है। यही कारण है कि इस बार का मानसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के स्तर पर विधायी कार्यों की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित विधेयकों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास, निवेश, सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ऐसे कानून बनाए जाएं, जो आने वाले वर्षों में देश की विकास यात्रा को नई दिशा दे सकें। वहीं विपक्ष इन प्रस्तावों को लेकर पहले से ही रणनीति बनाने में जुट गया है और संकेत दिए हैं कि प्रत्येक विधेयक का संवैधानिक, राजनीतिक और जनहित के आधार पर परीक्षण किया जाएगा।

सबसे अधिक चर्चा जिस प्रस्तावित कानून को लेकर हो रही है, वह भ्रष्टाचार-रोधी व्यवस्था को और मजबूत बनाने वाला विधेयक है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार जनप्रतिनिधियों तथा सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बदलाव चाहती है। प्रस्तावित कानून में जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, गंभीर मामलों में कार्रवाई को तेज करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकार का तर्क है कि इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि कानून का दायरा और उसके प्रावधान स्पष्ट होने के बाद ही वह अपना अंतिम रुख तय करेगा। विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि किसी भी नए कानून का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए।

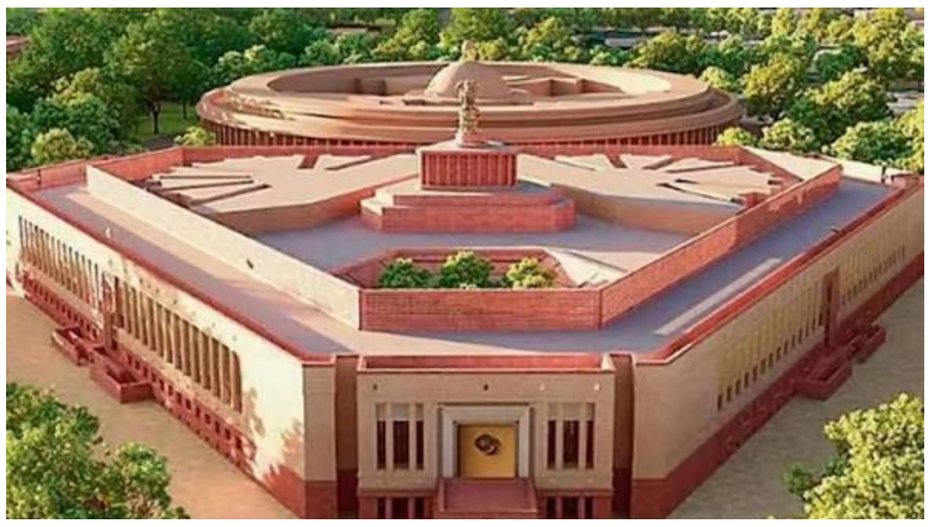

आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर सरकार पूंजी बाजार सुधार विधेयक को भी प्राथमिकता दे सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है और डिजिटल माध्यमों से निवेश का दायरा भी व्यापक हुआ है। ऐसे में सरकार नियामकीय व्यवस्था को आधुनिक बनाने, निवेशकों के हितों की सुरक्षा बढ़ाने, पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से नए प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह कानून लागू होता है तो विदेशी निवेश आकर्षित करने, स्टार्टअप कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने और घरेलू निवेश वातावरण को और अधिक मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े सुधार भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताए जा रहे हैं। कंपनी कानून (संशोधन) विधेयक के माध्यम से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाने, अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल करने तथा कारोबार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अत्यधिक नियामकीय बोझ कम होने से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप कंपनियों और नवाचार आधारित उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के विभिन्न प्रावधानों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा सुधार विधेयक ला सकती है। प्रस्तावित सुधारों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बढ़ाना, अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, डिजिटल शिक्षा को संस्थागत रूप देना, गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना तथा नियामकीय ढांचे को अधिक प्रभावी बनाना शामिल हो सकता है। सरकार का मानना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में भारतीय विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए व्यापक सुधार आवश्यक हैं। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े कई विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सुधारों के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और संस्थानों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा।

राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील और व्यापक चर्चा वाला विषय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। आगामी जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाली मानी जा रही है। यदि यह प्रस्ताव संसद में आता है तो इस पर व्यापक बहस होना तय माना जा रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने पहले ही चिंता व्यक्त की है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से संसद में उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है, जबकि अधिक आबादी वाले राज्यों को अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे में यह मुद्दा केवल संवैधानिक नहीं बल्कि संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन से भी जुड़ा माना जा रहा है। पिछले संसदीय सत्र में भी परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, लेकिन आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण वह पारित नहीं हो सका था। इस बार सरकार यदि इसे दोबारा लाती है तो राजनीतिक समीकरणों पर सबकी नजर रहेगी।

सरकार के सुधार एजेंडे का एक बड़ा उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को गति देना बताया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालयों का मानना है कि बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा के बिना जल्दबाजी में निर्णय लेने का प्रयास नहीं होना चाहिए। विपक्ष संसदीय समितियों के माध्यम से विस्तृत परीक्षण और व्यापक विमर्श की मांग कर सकता है।

संसदीय जानकारों का मानना है कि इस बार मानसून सत्र केवल विधेयकों के पारित होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकार और विपक्ष के बीच वैचारिक टकराव का भी प्रमुख मंच बनेगा। आर्थिक सुधार, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार-रोधी कानून, कॉर्पोरेट नियमन और चुनावी ढांचे जैसे विषय सीधे तौर पर देश की दीर्घकालिक नीतियों से जुड़े हैं। इसलिए संसद के भीतर होने वाली बहसों का असर आने वाले वर्षों की नीति-निर्माण प्रक्रिया पर भी दिखाई देगा।

देशभर की निगाहें अब संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं। सरकार इसे अपने सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर मान रही है, जबकि विपक्ष लोकतांत्रिक विमर्श और संवैधानिक संतुलन के मुद्दे पर सरकार को चुनौती देने की तैयारी में है। ऐसे में यह सत्र केवल विधायी गतिविधियों का मंच नहीं, बल्कि देश की भावी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।

पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा अभियान, पुणे में 66 लोगों से पूछताछ

पुणे। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संभावित सीमा पार नेटवर्क के खिलाफ एक बड़े अभियान में पुणे जिले के विभिन्न हिस्सों में व्यापक तलाशी और पूछताछ शुरू की है। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर चलाए गए इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कथित नेटवर्क से जुड़े होने के संदेह में 66 लोगों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहन पड़ताल में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार, एटीएस को हाल के दिनों में ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि पाकिस्तान में सक्रिय कुछ आपराधिक और संदिग्ध तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सूचनाओं के सत्यापन के बाद एटीएस ने तकनीकी निगरानी, डिजिटल इनपुट और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुणे जिले में एक समन्वित अभियान चलाया। मंगलवार सुबह विभिन्न इलाकों में अलग-अलग टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की।

अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान केवल किसी आपराधिक मामले की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा बनाने, उन्हें भड़काने या देशविरोधी गतिविधियों के लिए प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। जांच एजेंसियां प्रत्येक व्यक्ति की डिजिटल गतिविधियों, संपर्क सूत्रों, सोशल मीडिया संवाद और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही हैं।

प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि शहजाद भट्टी कथित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय युवाओं से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। एजेंसियों को आशंका है कि ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर विश्वास कायम करने के बाद कुछ लोगों को नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई हो सकती है। हालांकि एटीएस ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

एटीएस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान यह भी जांचा जा रहा है कि संबंधित व्यक्तियों का इन ऑनलाइन संपर्कों से क्या संबंध था। यह पता लगाया जा रहा है कि बातचीत केवल सोशल मीडिया तक सीमित थी या उसके पीछे कोई संगठित गतिविधि, आर्थिक लेन-देन अथवा अन्य उद्देश्य भी मौजूद थे। जांच में साइबर विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है, ताकि डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जांच केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। यदि पूछताछ और डिजिटल विश्लेषण के दौरान अन्य राज्यों या विदेशी संपर्कों के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी जानकारी साझा की जाएगी। खुफिया विभाग इस बात की भी पड़ताल कर रहा है कि क्या इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान से संचालित अन्य संदिग्ध संगठनों या व्यक्तियों से जुड़े हैं।

जांच एजेंसियों का मानना है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सीमापार आपराधिक एवं संदिग्ध नेटवर्क नए लोगों तक पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण डिजिटल निगरानी और साइबर जांच को इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

एटीएस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी अज्ञात व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते समय सतर्क रहें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति देशविरोधी सामग्री साझा करता है, उकसाने वाले संदेश भेजता है या किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को दें। फिलहाल एटीएस की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। यदि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यदि पूछताछ में किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार मुक्त कर दिया जाएगा। जांच एजेंसियों का कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी सूचना को गंभीरता से लिया जाता है और प्रत्येक तथ्य का विधिसम्मत परीक्षण किया जाता है।

मोबाइल टावरों से करोड़ों की चोरी का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय सिंडिकेट का किया भंडाफोड़

नई दिल्ली। देश की दूरसंचार व्यवस्था को निशाना बनाकर मोबाइल टावरों से अत्याधुनिक उपकरण चोरी करने और उन्हें विदेश भेजने वाले एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में गिरोह के चार प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए करीब 70 लाख रुपये मूल्य की 43 रिमोट रेडियो यूनिट्स (आरआरयू) बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर महंगे नेटवर्क उपकरण चोरी कर रहा था और उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए एयर कार्गो से हांगकांग भेज रहा था। क्राइम ब्रांच के अनुसार इस कार्रवाई से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दर्ज 19 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस का मानना है कि यह केवल स्थानीय चोरी का मामला नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसकी कड़ियां विदेशों तक फैली हो सकती हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास पासवान (संगम विहार), हेमंत गुप्ता (हर्ष विहार), फरीद (गाजियाबाद) और शेर मोहम्मद (मेरठ) के रूप में हुई है। जांच के अनुसार विकास पासवान इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है, जो चोरी की योजना बनाने से लेकर उपकरणों को विदेश भेजने तक पूरे नेटवर्क का संचालन करता था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विभिन्न राज्यों से चोरी की गई रिमोट रेडियो यूनिट्स को दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र में एकत्र कर विदेश भेजने की तैयारी चल रही है। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि चोरी के उपकरणों की एक बड़ी खेप महिपालपुर स्थित एक कूरियर एजेंसी के माध्यम से एयर कार्गो द्वारा हांगकांग भेजी जाने वाली है। सूचना की पुष्टि होते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने महिपालपुर स्थित गोदाम और कूरियर कार्यालय के आसपास जाल बिछाया। सबसे पहले पुलिस ने हेमंत गुप्ता को एक वाहन सहित पकड़ा, जिसमें 19 चोरी की आरआरयू यूनिट्स रखी हुई थीं। पूछताछ और मौके पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विकास पासवान को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ समय बाद मेरठ और गाजियाबाद से फरीद तथा शेर मोहम्मद एक कार में वहां पहुंचे। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें से नौ अतिरिक्त आरआरयू बरामद हुईं। इसके बाद गोदाम की तलाशी में चार और यूनिट्स मिलीं। इसी दौरान एक पोर्टर वाहन में 11 अन्य आरआरयू लेकर वहां पहुंचा, जिन्हें पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया। इस तरह कुल 43 चोरी की गई रिमोट रेडियो यूनिट्स बरामद की गईं। पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह पिछले आठ से नौ महीनों से लगातार सक्रिय था और अब तक 800 से अधिक आरआरयू यूनिट्स चोरी कर विदेश भेज चुका है। चोरी किए गए उपकरणों को पहले दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में स्थित गोदामों में छिपाकर रखा जाता था। इसके बाद फर्जी बिल, नकली दस्तावेज और गलत घोषणाओं के जरिए इन्हें एयर कार्गो से हांगकांग भेज दिया जाता था, जहां इन्हें आगे बेचा जाता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में उपकरणों का विदेश भेजा जाना इस बात का संकेत है कि गिरोह के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत संपर्क थे। अब पुलिस उन कंपनियों, एजेंटों और विदेशी खरीदारों की पहचान करने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने इन चोरी के उपकरणों की खरीद की। इसके लिए सीमा शुल्क विभाग, एयर कार्गो एजेंसियों और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी समन्वय किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू) मोबाइल टावरों का अत्यंत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। यह मोबाइल नेटवर्क के रेडियो सिग्नल के प्रसारण और रिसेप्शन का मुख्य हिस्सा होता है। किसी टावर से इसके चोरी हो जाने पर उस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ सकती है और इंटरनेट सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। यही कारण है कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे मामलों में भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ सेवा बाधित होने की चुनौती भी झेलनी पड़ती है। प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि गिरोह पहले ऐसे मोबाइल टावरों की पहचान करता था जहां सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर होती थी। रात के समय या सुनसान इलाकों में स्थित टावरों से उपकरण निकाल लिए जाते थे और बाद में उन्हें अलग-अलग स्थानों पर पहुंचाकर गोदामों में जमा किया जाता था। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगा रही हैं कि क्या इस गिरोह को टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े किसी अंदरूनी व्यक्ति की भी मदद मिल रही थी। क्राइम ब्रांच ने मामले में आगे की जांच तेज कर दी है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, चोरी के पूरे नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों, एयर कार्गो के जरिए उपकरण भेजने में सहयोग करने वाले लोगों तथा विदेश में मौजूद खरीदारों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

थोक महंगाई ने तोड़ा 44 महीनों का रिकॉर्ड रसोई से उद्योग तक बढ़ेगा महंगाई का दबाव

नई दिल्ली। देश में महंगाई का दबाव लगातार गहराता जा रहा है। जून 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई बढ़कर 9.81 प्रतिशत (सरकारी ताजा आंकड़ों के अनुसार लगभग 9.8 प्रतिशत के स्तर) पर पहुंच गई, जो पिछले 44 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले सितंबर 2022 में थोक महंगाई दोहरे अंक में पहुंची थी। लगातार बढ़ती थोक महंगाई ने उद्योग, व्यापार और आम उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे माल, खाद्य पदार्थों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में कीमतों का दबाव इसी तरह बना रहा तो आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई पर भी इसका व्यापक असर दिखाई दे सकता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मई की तुलना में जून में थोक महंगाई में और तेजी दर्ज की गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खाद्य वस्तुओं, कृषि उत्पादों और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने भी लागत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि वैश्विक परिस्थितियों में जल्द सुधार नहीं होता, तो ईंधन, परिवहन और उत्पादन लागत में और वृद्धि हो सकती है।

सबसे अधिक असर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ा है। प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध तथा अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थोक बाजार में लागत बढ़ी है। खाद्य

सूचकांक (फूड इंडेक्स) भी लगातार ऊपर गया है, जिसका सीधा प्रभाव घरेलू रसोई के बजट पर पड़ रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि थोक स्तर पर खाद्य कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो खुदरा बाजार में भी इनके दाम और बढ़ सकते हैं।

हालांकि ईंधन एवं ऊर्जा क्षेत्र में कुछ राहत देखने को मिली है। फ्यूल और पावर श्रेणी की महंगाई दर में पहले की तुलना में कुछ कमी दर्ज हुई है, लेकिन यह अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें और समुद्री परिवहन लागत उद्योगों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की महंगाई दर में उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उद्योगों का कहना है कि कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत का दबाव लगातार बना हुआ है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, थोक महंगाई का असर कुछ समय बाद खुदरा महंगाई पर दिखाई देता है। जब उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ती है तो कंपनियां धीरे-धीरे उस अतिरिक्त खर्च को उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर देती हैं। यही कारण है कि आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों, उपभोक्ता वस्तुओं, निर्माण सामग्री, घरेलू उपकरणों और अन्य आवश्यक सामानों की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

इससे पहले जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई थी। जून में खुदरा महंगाई लगातार छठे महीने बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई। जनवरी में यह केवल 2.74 प्रतिशत थी, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रत्येक महीने इसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। मई में खुदरा महंगाई 3.93 प्रतिशत थी, जो जून में और ऊपर चली गई। इसका सबसे बड़ा कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि माना जा रहा है।

विशेष रूप से आलू, अदरक, प्याज, हरी सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी ने उपभोक्ताओं का बजट बिगाड़ दिया है। कई राज्यों में मौसम संबंधी चुनौतियों, परिवहन लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव के कारण बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं। यदि मानसून के दौरान फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो खाद्य महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

उद्योग जगत का मानना है कि लगातार बढ़ती थोक महंगाई उत्पादन लागत को प्रभावित कर रही है। इस्पात, सीमेंट, रसायन, प्लास्टिक, रबर और धातु जैसे क्षेत्रों में कच्चे माल की कीमतें पहले से ही ऊंचे स्तर पर हैं। ऐसे में छोटे और मध्यम उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। यदि लागत बढ़ती रही तो उत्पादों की कीमतों में संशोधन करना कंपनियों की मजबूरी बन सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि थोक मूल्य सूचकांक का सबसे अधिक प्रभाव उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ता है, जबकि खुदरा महंगाई सीधे आम उपभोक्ता की जेब पर असर डालती है। जब दोनों सूचकांक लगातार बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। ऐसे समय में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों को संतुलित रणनीति अपनानी पड़ती है, ताकि आर्थिक विकास की गति भी बनी रहे और महंगाई भी नियंत्रण में रहे।

सरकार के पास थोक महंगाई को नियंत्रित करने के सीमित विकल्प होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आयात शुल्क और करों में बदलाव, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने, बफर स्टॉक जारी करने तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने पर सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर राहत देने का प्रयास किया था। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ महीने महंगाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में स्थिरता आती है, मानसून सामान्य रहता है और कृषि उत्पादन बेहतर होता है तो कीमतों पर कुछ नियंत्रण संभव है। लेकिन यदि वैश्विक तनाव, ऊर्जा संकट और खाद्य आपूर्ति पर दबाव जारी रहता है तो महंगाई का असर उद्योगों से लेकर आम परिवारों तक और गहरा हो सकता है। लगातार बढ़ती थोक और खुदरा महंगाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि महंगाई का दबाव अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले महीनों में सरकार की आर्थिक नीतियों, आपूर्ति प्रबंधन और वैश्विक परिस्थितियों पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी।

संपादकीय

दुनिया में जंग, जेब में दंग

दुनिया के बड़े नेताओं की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनके एक बयान से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था करवट बदल लेती है। कल तक जो लोग शांति की बातें कर रहे थे, आज वही युद्ध की नई तारीख बता रहे हैं। सीज़फायर अब समझौता कम और मोबाइल रिचार्ज जैसा ज्यादा लगने लगा है—कुछ दिन चलता है, फिर खत्म हो जाता है। हर बार उम्मीद जगती है कि अब सब सामान्य होगा, लेकिन अगले ही पल कोई नया बयान, नया हमला और नई चिंता सामने आ जाती है।

युद्ध किसी और की धरती पर होता है, लेकिन उसकी गूंज सबसे पहले हमारी जेब में सुनाई देती है। मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर चलती हैं और पेट्रोल पंप पर बोर्ड बदल जाता है। ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्शन लगाया हुआ है। उधर धमाका हुआ नहीं कि इधर कीमतें अपडेट हो जाती हैं। आम आदमी सोचता रह जाता है कि उसने आखिर किस मोर्चे पर हार मानी थी, जिसकी सजा उसे रोज़ भरनी पड़ रही है।

पेट्रोल के दामों का अपना अलग संविधान है। न इन्हें मौसम से फर्क पड़ता है, न सरकारों से और न ही सीज़फायर से। इनके लिए हर दिन शुभ मुहूर्त होता है। कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला मिलता है, कभी डॉलर का और कभी कच्चे तेल का। कारण बदलते रहते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा एक ही रहता है—जेब हल्की और बाइक की टंकी आधी।

शेयर बाजार भी अब किसी रहस्य फिल्म की कहानी बन चुका है। अच्छी खबर आए तो निवेशक डर जाते हैं और बुरी खबर आए तो खरीदारी शुरू हो जाती है। पहले लोग युद्ध से घबराते थे, अब उसे "मार्केट मूवमेंट" कहते हैं। लगता है बाजार ने भी तय कर लिया है कि डरने से अच्छा है ट्रेडिंग कर लो। दुनिया चाहे तनाव में हो, निवेशक अवसर ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। उधर मानसून ने भी इस बार अपना मूड बदल लिया है। कहीं बादल ऐसे बरसते हैं कि नाव चलाने की नौबत आ जाए और कहीं किसान आसमान देखकर बादलों से दोस्ती करने की कोशिश करता रहता है। मौसम विभाग रोज़ नई भविष्यवाणी करता है और जनता रोज़ नया अनुभव। आखिरकार मौसम भी अब सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह हो गया है—हर घंटे बदलता रहता है। हमारे शहरों का हाल तो बारिश की पहली फुहार ही बता देती है। जिन सड़कों का उद्घाटन कुछ महीने पहले हुआ था, वे अचानक गड्ढों की प्रदर्शनी बन जाती हैं। पानी इतना भर जाता है कि लोग गूगल मैप नहीं, नाव खोजने लगते हैं। नगर निगम हर साल दावा करता है कि इस बार जलभराव नहीं होगा और बारिश हर साल साबित कर देती है कि प्रकृति किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होती। स्मार्ट सिटी का सपना भी बड़ा रोचक है। हर चौराहे पर "वर्क इन प्रोग्रेस" का बोर्ड वर्षों तक खड़ा रहता है। कभी-कभी लगता है कि बोर्ड लगाने वाली कंपनी ही सबसे ज्यादा प्रगति कर रही है। सड़क कब बनेगी, यह किसी को नहीं पता, लेकिन बोर्ड देखकर जनता को भरोसा जरूर रहता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। बाढ़ भी अब सरकारी कैलेंडर की सबसे समयनिष्ठ घटना बन चुकी है। ट्रेनें लेट हो सकती हैं, योजनाएं लेट हो सकती हैं, लेकिन बाढ़ कभी लेट नहीं होती। हर साल तय समय पर आती है और लोगों को याद दिलाकर चली जाती है कि जल निकासी की फाइलें अभी भी दफ्तरों में तैर रही हैं। सोने की कीमतों ने तो आम आदमी के सपनों को भी महंगा बना दिया है। पहले लोग गहने खरीदने दुकान जाते थे, अब सिर्फ रेट पूछकर लौट आते हैं। सुनार भी मुस्कुराकर कह देता है—"सोना बाद में खरीद लीजिए, अभी फोटो खिंचवा लीजिए।" ऐसा दौर आ गया है कि शादी में गहनों से ज्यादा उनकी ईएमआई की चर्चा होती है। खेलों में भी भारतीयों की रुचि अद्भुत है। फुटबॉल विश्व कप में भारत नहीं खेल रहा, फिर भी करोड़ों लोग पूरे उत्साह से मैच देख रहे हैं। दरअसल भारतीय दर्शक किसी भी दृश्य को रोचक बना सकते हैं। सड़क किनारे जेसीबी मशीन मिट्टी खोद रही हो, वहां भी मिनटों में दर्शक दीर्घा तैयार हो जाती है। शायद यही वजह है कि दुनिया को खिलाड़ी कम और दर्शक ज्यादा भारत से मिलते हैं। कुल मिलाकर दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, लेकिन आम आदमी की कहानी वही है। वह हर सुबह महंगाई से जूझता है, दोपहर में ट्रैफिक से लड़ता है, शाम को पेट्रोल भरवाता है और रात में खबरें देखकर अगले दिन की चिंता करता है। फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है।

आंतरिक संरचना की मजबूती से सुधरेगी आर्थिकी

> "आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए सरकार को अपने पूंजीगत व्यय को लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कारगर बनाना होगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं—जैसे रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नए बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी।

हाल ही में अमेरिका से सैन्य टकराव के बाद ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट के बंद किए जाने से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और बाजार जोखिमें भी बढ़ गई हैं। इससे एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर बढ़ने लगा है। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशियाई संकट और लॉजिस्टिक कीमतों में बढ़ोतरी का भारत की विकास दर पर प्रतिकूल असर होगा। ऐसे में एडीबी ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व निर्धारित 6.9 प्रतिशत विकास दर को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ का मानना है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतें भारत में आर्थिक चुनौतियां बढ़ा सकती हैं।

पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7 प्रतिशत की शानदार दर से वृद्धि दर्ज की थी, जो कि 2024-25 की 7.1 प्रतिशत की दर से काफी बेहतर थी। निःसंदेह इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू आर्थिक मुश्किलों के बीच अर्थव्यवस्था को गतिशील रखना और विकास दर बढ़ाना चुनौती है। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सरकार को 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के मंत्र को और अधिक आक्रामक ढंग से उपयोग में लाना होगा। वैश्विक झटके और तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत को अपनी समष्टि-आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्रीय बैंक

को अब महंगाई को नियंत्रण में रखने के साथ-साथ विकास की गति को थमने से बचाना होगा।

ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए सरकार को अपने पूंजीगत व्यय को लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कारगर बनाना होगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं—जैसे रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नए बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश बढ़ने से इस्पात, सीमेंट और निर्माण जैसे मुख्य क्षेत्रों में मांग बनी रहती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता रहता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नए सिरे से व्यवधान आने की आशंका को देखते हुए भारत को घरेलू विनिर्माण पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का दायरा बढ़ाकर उन क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए जो आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं।

अब बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को भी ढाल बनाना होगा। अप्रैल-मई 2026 में भारत का निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत द्वारा तेजी से बढ़ाए जा रहे 'मुक्त व्यापार समझौते' नए बाजार खोलने में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले साबित हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत आगामी 10 महीनों में 9 नए व्यापार समझौतों को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। 1 जून, 2026 से भारत और ओमान के बीच वृहद आर्थिक एवं साझेदारी समझौता पूरी तरह लागू हो चुका है। इससे ओमान में भारत के 99 प्रतिशत से अधिक उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश मिल रहा है।

ब्रिटेन के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते का क्रियान्वयन इसी माह 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह भारतीय कपड़ा, फार्मा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा संवर्धक साबित होगा। इसके साथ ही न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए शीघ्र कार्यान्वित होगा। अमेरिका के साथ भी वार्ता अंतिम दौर में है। मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ समझौतों के लाभ जमीन पर दिखने लगे हैं। इसके अलावा कनाडा, इस्राइल, रूस और पेरू जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी व्यापार वार्ताओं में तेजी लाई गई है।

निश्चित रूप से बाहरी झटकों से निपटने के लिए भारत ने अपनी आंतरिक संरचना को पहले से मजबूत किया है। देशभर में जमीनी स्तर पर चार नई श्रम संहिताओं के तहत लागू हुए नए सरल श्रम कानून विनिर्माण क्षेत्र में 'व्यापार सुगमता' को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इनसे न केवल विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है, बल्कि वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में काम करना आसान हुआ है।

यदि सरकार इस वर्ष के बजट में विनिवेश के लिए निर्धारित 80 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य को समय पर प्राप्त कर लेती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को और अधिक उदार बनाती है तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है, तो भारत की आर्थिक गतिशीलता को बचाया जा सकेगा।

प्रेरणा

स्वप्नों में गूंजती गुरु-वाणी: साधना, संस्कार और संगीत की अमर परंपरा

भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल स्वरों का विज्ञान नहीं है, बल्कि वह साधना, श्रद्धा, संस्कार और आत्मिक अनुभूति का ऐसा संगम है, जहां गुरु और शिष्य का संबंध समय और मृत्यु की सीमाओं से भी आगे बढ़ जाता है। हमारे देश की संगीत परंपरा में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जो यह विश्वास जगाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या औपचारिक शिक्षा से नहीं मिलता, बल्कि वह गुरु की कृपा, निरंतर अभ्यास और आत्मिक जुड़ाव से प्राप्त होता है। जब शिष्य पूरी निष्ठा, समर्पण और विश्वास के साथ साधना करता है, तब गुरु का मार्गदर्शन उसके जीवन का ऐसा प्रकाश बन जाता है, जो हर कठिन मोड़ पर दिशा दिखाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही उस ज्ञान के द्वार खोलते हैं, जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है।

बनारस घराने की महान ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी और उनकी सुपुत्री सविता देवी की जीवन-यात्रा इसी गुरु-शिष्य परंपरा की एक अद्भुत मिसाल है। यह केवल मां-बेटी का संबंध नहीं था, बल्कि एक ऐसी संगीत-साधना का रिश्ता था, जिसमें संस्कार, समर्पण और आत्मिक ऊर्जा का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। सिद्धेश्वरी देवी ने अपने जीवनकाल में अपनी बेटी को जितना संगीत सिखाया, उससे कहीं अधिक गहरी प्रेरणा उन्होंने अपने जाने के बाद भी दी। यह घटना केवल एक भावनात्मक संस्मरण नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। उसका आशीर्वाद, उसका ज्ञान और उसकी प्रेरणा हर परिस्थिति में शिष्य के साथ बनी रहती है।

कहा जाता है कि सिद्धेश्वरी देवी के निधन के बाद भी सविता देवी को अक्सर ऐसे स्वप्न आते थे, जिनमें उनकी मां उन्हें नई-नई ठुमरियां, बंदिशें, आलाप और लयकारी सिखाती थीं। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होते थे। वह न पूरी तरह गहरी नींद की अवस्था होती थी और न ही पूर्ण जाग्रत अवस्था। यह दोनों के बीच की एक ऐसी तंद्रा होती थी, जहां चेतना किसी अदृश्य संसार से जुड़ती हुई प्रतीत होती थी। उन क्षणों में मां का स्वर, उनका स्नेह और उनका संगीत मानो उसी प्रकार उपस्थित हो जाता था, जैसे वे जीवन में सामने बैठकर शिक्षा दे रही हों।

जब सविता देवी जागने के बाद उन्हीं बंदिशों को गाने का प्रयास करतीं, तो उन्हें आश्चर्य होता कि हर स्वर, हर आलाप और हर लय उसी प्रकार स्मरण है, जैसा स्वप्न में सुनाया गया था। उनकी गायकी में ऐसी मिठास, ऐसी आत्मीयता और ऐसा भाव उतर आता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। यह केवल तकनीकी दक्षता नहीं थी, बल्कि उसमें आत्मा की अनुभूति थी। यही कारण था कि उनकी ठुमरी केवल कानों को नहीं, बल्कि सीधे हृदय को स्पर्श करती थी।

भारतीय संगीत में यह विश्वास प्राचीन काल से रहा है कि जब साधना अपने चरम पर पहुंचती है, तब कलाकार केवल अभ्यास नहीं करता, बल्कि संगीत उसके भीतर स्वयं प्रवाहित होने लगता है। तब रचना बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से जन्म लेती है। गुरु की शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह शिष्य के संस्कारों का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि कई महान कलाकारों ने स्वीकार किया है कि मंच पर प्रस्तुति देते समय उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो।

सविता देवी के जीवन में भी ऐसा ही एक प्रसंग आया। बनारस में एक अत्यंत प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलन आयोजित होने वाला था। देश के अनेक नामचीन संगीतज्ञ उसमें आमंत्रित थे। शहनाई के महान उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसे दिग्गज कलाकार भी उसमें उपस्थित थे। ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति देना किसी भी कलाकार के लिए सम्मान के साथ-साथ चुनौती भी होती है। स्वाभाविक रूप से सविता देवी भी मन ही मन थोड़ी चिंतित थीं। उन्हें चिंता थी कि इतने बड़े कलाकारों के बीच उनकी प्रस्तुति कैसी होगी और क्या वे श्रोताओं की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएंगी।

उस रात उन्हें फिर अपनी मां का स्वप्न आया। सिद्धेश्वरी देवी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, "तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक होगा।" स्वप्न में उन्होंने यह भी देखा कि वे अपनी मां के साथ सीढ़ियां चढ़ रही हैं। कुछ ही क्षण बाद उनकी आंख खुल गई। यह स्वप्न केवल सांत्वना नहीं था, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास का नया संचार कर गया। अगले दिन जब वे मंच पर पहुंचीं, तो उनकी प्रस्तुति ने उपस्थित श्रोताओं और संगीतज्ञों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी ठुमरी में ऐसा माधुर्य, ऐसी परिपक्वता और ऐसा भाव था कि सभा देर तक तालियों से गूंजती रही। उन्हें भरपूर सराहना मिली और वह संगीत सम्मेलन उनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया।

इस प्रसंग को केवल चमत्कार कहकर टाल देना उचित नहीं होगा। वास्तव में यह उस गहरे मानसिक और आध्यात्मिक संबंध का प्रमाण है, जो गुरु और शिष्य के बीच वर्षों की साधना से निर्मित होता है। जब कोई शिष्य पूरे मन से गुरु के ज्ञान को आत्मसात करता है, तब वह ज्ञान उसके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाता है। कठिन समय में वही संस्कार उसे सही दिशा दिखाते हैं। कई बार मन उसे स्वप्न के रूप में अनुभव करता है, तो कई बार अंतःप्रेरणा के रूप में।

भारतीय संस्कृति में स्वप्नों को भी केवल कल्पना नहीं माना गया है। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जहां स्वप्न प्रेरणा, मार्गदर्शन और चेतावनी का माध्यम बने हैं। विशेषकर जब मन निर्मल हो, जीवन अनुशासित हो और साधना निरंतर हो, तब स्वप्न केवल मानसिक चित्र नहीं रहते, बल्कि आत्मिक अनुभव का माध्यम बन सकते हैं। कलाकारों, संतों और साधकों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं।

संगीत स्वयं भी एक आध्यात्मिक साधना है। जब कलाकार वर्षों तक रियाज करता है, तब उसका संबंध केवल स्वरों से नहीं रहता, बल्कि वह अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगता है। उसी अवस्था में कला ईश्वर की उपासना बन जाती है। तब मंच केवल प्रदर्शन का स्थान नहीं रहता, बल्कि साधना का मंदिर बन जाता है। ऐसे कलाकार अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं, बल्कि अपने गुरु, अपने संस्कार और ईश्वर की कृपा को देते हैं। आज के समय में, जब त्वरित सफलता की चाह ने धैर्य और साधना का महत्व कम कर दिया है, सिद्धेश्वरी देवी और सविता देवी की यह प्रेरक कथा हमें याद दिलाती है कि किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। उसके लिए निरंतर अभ्यास, गुरु के प्रति श्रद्धा, विनम्रता और आत्मविश्वास आवश्यक है। तकनीक हमें जानकारी दे सकती है, लेकिन अनुभव, संवेदना और संस्कार केवल समर्पण से प्राप्त होते हैं। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि माता-पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, बल्कि वे हमारे पहले गुरु भी होते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कारों पर गार्जियन की हताशा

दा गार्जियन अखबार ने मोदी और भारत की छवि धूमिल करने के लिए एक अंग्रेजी मे एक लेख लिखा। जिसका सारांश यह है कि कोई झूठे भी पुरस्कार देने के लिए बुलाए तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मतलब यह अखबार कहना चाह रहा कि मोदी पुरस्कार के भूखे हैं, साथ ही यह भी जताने की कोशिश कर रहा है, जिन देशों ने मोदी को उनकी विदेश यात्रा के दौरान पुरस्कार दिए, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को इन देशों ने फिजूल में पुरस्कार दिए हैं। गार्जियन ने यह लेख लिख कर मोदी सहित भारत का तो अपमान किया ही है, साथ मोदी को पुरस्कार देने वाले उन देशों के नागरिकों, पुरस्कारों और उन देशों के राष्ट्रप्रमुखों का भी अपमान किया है।इस लेख की भड़ास के बावजूद पीएम मोदी को पुरस्कारों का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रदान किया। वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों से ऐसे 34 सम्मान मिल चुके हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले सम्मानों में सबसे अधिक हैं। इनमें से कुछ सम्मान सदियों पुराने हैं, जबकि कुछ सम्मान संबंधित देशों की सम्मान प्रणाली में हाल ही में शामिल किए गए हैं।

गार्जियन का यह लेख में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। विश्व का बड़ा और प्रभावशाली शायद ही कोई देश बचा होगा जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मोदी और भारत की तारीफ नहीं की होगी। दरअसल यह तारीफ पाश्चात्य मीडिया पचा नहीं पा रहा है, पचा इसलिए भी नहीं पा रहा है कि भारत न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तरक्की के झंडे गाढ़ रहा है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन की कामयाबी इसके बड़े उदाहरण हैं। जो विकसित देश भी हासिल नहीं कर सके। यह अखबार यह भी भूल गया कि जब कोरोना काल में पूरी दुनियां में हाहाकार मचा हुआ था, तब भारत ने ही कोरोना वैक्सीन दर्जनों देशों को निशुल्क भेज कर करोड़ों लोगों की जाने बचाने का काम किया था। क्या ऐसे परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें विदेशी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता।

गार्जियन ने इसका जिक्र कभी नही किया कि विश्व को मोदी नेतृत्व में भारत ने क्या—क्या दिया है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सस्ती और सुलभ डिजिटल पेमेंट प्रणाली नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस ने अपना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की प्राचीन धरोहर योग को मोदी सरकार के प्रयासों से वैश्विक मान्यता मिलीसंयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।

भारत ने प्राकृतिक आपदा के दौरान विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है। तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप के दौरान'मिशन सागर'और'ऑपरेशन दोस्त'के जरिए विश्व स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत बचाव दल और पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा (2025) और ऑपरेशन सहायता (2008) के तहत भूकंप व चक्रवात के दौरान भारी राहत सामग्री व चिकित्सा सुविधाएँ दी गईं। श्रीलंका में सुनामी (2004) में ऑपरेशन रेनबो और चक्रवात (2025) में ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री सुरक्षा अभियानों (मुख्य रूप से अरब सागर और अदन की खाड़ी) में 520 से अधिक लोगों की जान बचाई है और ईरान, लाइबेरिया, माल्टा, और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स जैसे विभिन्न देशों के झंडे वाले जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित मुक्त कराया है। इन अभियानों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि नौसेना ने बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के, पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों सहित कई देशों के नाविकों को भी बचाया है।

गार्जियन खासकर विदेशी मीडिया को कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारी परेशानी है। भारत में उन्हें यह उल्लंघन नजर आता है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। अंग्रेज शासकों ने इस अवधि में भारतीयों पर अत्याचारों के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। अंग्रेज व्यापारी बन कर आए और तानाशाह बन बैठे, खूब लूट खसौट की और भारत से सारा मालमत्ता समेट कर चंपत हो गए। आज भी कोहिनूर का हीरा इन्हीं अंग्रेजों के पास है, जो यह बताता है कि किस तरह इन्होंने भारत में लूटपाट मचाई थी। ऐसे मानवाधिकारों के उल्लंघन गार्जियन जैसे अखबारों को दिखाई नहीं देते। मानवाधिकारों के इन विदेशी पैरोकारों को जलियांवाला बाग दिखाई नहीं देता, जहां निहत्थे प्रदर्शकारियों को चारों तरफ से घेर कर एक अंग्रेज अधिकारी डायर ने गोलियों से भून डाला था।

गार्जियन को यह कभी दिखाई नहीं दिया कि किस तरह केंद्र सरकार ने मुसलमानों की भलाई का एक ऐतिहासिक काम किया, जिसे करने से पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री डरते रहे। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मिलने वाला कानून हक दिलवाया है। जिन्हें पहले पति तीन बार तलाक तलाक बोल कर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था।कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट के डर से सुप्रीम कोर्ट के शाह बानों के फैसले को ही पलट दिया था, जिसमें कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, इसके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कानून बना दिया था।

विदेशी अखबारों को तकलीफ हो रही है कि मोदी राज में कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जब भारत ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तब खीझ उतारने के लिए कह दिया कि मोदी पुरस्कार के लिए दौड़े चले आते हैं। जिला स्तर, वार्ड स्तर, राज्यस्तर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी क्षेत्र में पुरस्कार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन्हें पाने के लिए लोग अपनी पूरी उम्र खपा देते हैं। उसमें भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है, तब कहीं जाकर किसी एक का चयन किया जाता है।

अभियान

दिव्य शक्ति का गूढ़ विज्ञान: गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की साधना क्यों मानी जाती है आध्यात्मिक जागरण का सर्वोच्च मार्ग

सनातन धर्म की विशाल आध्यात्मिक परंपरा में शक्ति की उपासना का स्थान सर्वोपरि माना गया है। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार की मूल चेतना को आदिशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में देवी की आराधना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन की साधना मानी जाती है। वर्षभर में आने वाली चार नवरात्रियों में चैत्र और शारदीय नवरात्रि व्यापक रूप से मनाई जाती हैं, लेकिन आषाढ़ और माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट और रहस्यमय माना गया है। यह ऐसा पर्व है जिसमें बाहरी उत्सव से अधिक महत्व आंतरिक साधना, आत्मचिंतन, मौन, संयम और ईश्वरीय शक्ति के साथ आत्मिक जुड़ाव को दिया जाता है। वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक रहेगी। इन नौ दिनों को शक्ति साधना, मंत्र-जप, ध्यान, आत्मशुद्धि और दस महाविद्याओं की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।

गुप्त नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इसे "गुप्त" क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सनातन साधना की उस परंपरा में छिपा है, जहां आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संरक्षण किया जाता है। प्राचीन ऋषियों और तांत्रिक आचार्यों का मत था कि साधना का वास्तविक प्रभाव तब प्रकट होता है जब वह पूर्ण श्रद्धा, मौन और गोपनीयता के साथ की जाए। इसलिए इस अवधि में किए जाने वाले जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान को यथासंभव गुप्त रखा जाता है। इसका उद्देश्य रहस्य पैदा करना नहीं, बल्कि साधक के भीतर विनम्रता बनाए रखना और साधना की ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाना है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि को आत्मशक्ति के जागरण का पर्व कहा गया है।

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ रूपों के साथ-साथ शक्ति के दस अत्यंत दिव्य और रहस्यमय स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिन्हें दस महाविद्याएं कहा जाता है। ये केवल देवी के अलग-अलग रूप नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के दस महान सिद्धांतों, दस प्रकार की चेतनाओं और जीवन के दस आध्यात्मिक आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक महाविद्या साधक के भीतर किसी विशेष शक्ति का जागरण करती है और उसे जीवन की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है।

दस महाविद्याओं की उत्पत्ति से जुड़ी कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थीं और भगवान शिव ने उन्हें रोकना चाहा, तब देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से दस दिशाओं में अपने दस स्वरूप प्रकट कर दिए। उन दस स्वरूपों ने भगवान शिव को चारों ओर से घेर लिया और वे किसी भी दिशा में नहीं जा सके। यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक दिशा, प्रत्येक ऊर्जा और प्रत्येक शक्ति देवी के विभिन्न रूपों से ही संचालित होती है।

दस महाविद्याओं में सबसे पहले मां काली का नाम आता है। मां काली को समय, मृत्यु, निर्भयता और परिवर्तन की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना भय और अहंकार होता है। जो व्यक्ति इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मां काली की आराधना से मानसिक साहस, आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होने की मान्यता है।

मां तारा दूसरी महाविद्या हैं। वे करुणा, ज्ञान, संरक्षण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की देवी मानी जाती हैं। तारा का अर्थ ही है—पार लगाने वाली। अर्थात जो साधक को अज्ञान, भ्रम और संकटों से निकालकर सत्य के मार्ग पर ले जाए। उनकी उपासना से मानसिक शांति, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।

मां त्रिपुर सुंदरी को श्रीविद्या की अधिष्ठात्री माना गया है। उनका स्वरूप केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि संतुलन, प्रेम, आनंद और परम चेतना का प्रतीक है। वे यह संदेश देती हैं कि वास्तविक सुंदरता व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और आत्मा की पवित्रता में होती है। उनकी कृपा से जीवन में सामंजस्य, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होने की मान्यता है।

मां भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती हैं। उनका स्वरूप यह बताता है कि समस्त जगत देवी की चेतना में ही स्थित है। वे व्यापक दृष्टिकोण, धैर्य, नेतृत्व और स्थिरता का प्रतीक हैं। जो लोग बड़े दायित्वों का निर्वहन करते हैं या जीवन में नई दिशा तलाश रहे होते हैं, उनके लिए मां भुवनेश्वरी की आराधना विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है।

मां छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और गूढ़ है। पहली दृष्टि में यह स्वरूप विचित्र लग सकता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। यह आत्मबलिदान, इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मबोध का प्रतीक है। उनका संदेश है कि जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग नहीं करता, तब तक वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।

मां त्रिपुर भैरवी तप, अनुशासन, परिश्रम और आत्मबल की देवी हैं। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन की कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना निरंतर अभ्यास, संयम और कठिन परिश्रम के संभव नहीं है। उनकी आराधना साधक के भीतर दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छाशक्ति का विकास करती है।

मां धूमावती को वैराग्य और आत्मचिंतन की देवी कहा जाता है। वे संसार की अस्थिरता और नश्वरता का बोध कराती हैं। उनका स्वरूप यह प्रेरणा देता है कि जीवन में मोह, लालच और अनावश्यक आसक्तियों से मुक्त होकर ही वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। उनकी साधना व्यक्ति को आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाती है।

मां बगलामुखी को वाणी, आत्मरक्षा और शत्रु-विजय की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उनकी कृपा से विरोधी शक्तियां शांत होती हैं और व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। न्यायिक विवाद, प्रतियोगिता और कठिन परिस्थितियों में उनकी आराधना विशेष रूप से की जाती है।

मां मातंगी ज्ञान, कला, संगीत, साहित्य और वाणी की देवी हैं। वे यह संदेश देती हैं कि ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समाज और मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। विद्यार्थी, कलाकार, लेखक, शोधकर्ता और संगीत साधक विशेष रूप से उनकी उपासना करते हैं।

दसवीं महाविद्या मां कमला हैं, जिन्हें महालक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप माना गया है। वे धन, समृद्धि, सौभाग्य, संतोष और आध्यात्मिक सम्पन्नता की प्रतीक हैं। उनकी आराधना से केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होता है।

गुप्त नवरात्रि में पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार शुद्ध मन और सात्विक जीवन माना गया है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इन नौ दिनों में सात्विक भोजन करना, क्रोध और कटु वाणी से बचना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियमित ध्यान करना तथा देवी के मंत्रों का श्रद्धा के साथ जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो नौ दिनों तक अखंड दीप प्रज्ज्वलित रखना भी विशेष फलदायी माना गया है। पूजा के समय स्वच्छ वस्त्र धारण कर देवी को पुष्प, फल, नैवेद्य और दीप अर्पित किए जाते हैं। अनेक श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, ललिता सहस्रनाम और सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करते हैं।

हालांकि धार्मिक विद्वान यह भी स्पष्ट करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में वर्णित कई तांत्रिक साधनाएं अत्यंत जटिल होती हैं और उन्हें केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। बिना दीक्षा और उचित ज्ञान के किसी भी विशेष तांत्रिक अनुष्ठान का प्रयास करना उचित नहीं माना गया है। सामान्य गृहस्थ के लिए श्रद्धा, भक्ति, जप, ध्यान, दान, सेवा और आत्मसंयम ही सबसे श्रेष्ठ साधना है।

गुप्त नवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपी दिव्य चेतना का जागरण है। दस महाविद्याएं हमें जीवन के दस महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं—निर्भयता, करुणा, संतुलन, व्यापक दृष्टि, त्याग, अनुशासन, वैराग्य, आत्मरक्षा, ज्ञान और समृद्धि। यदि साधक इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले, तो उसकी साधना स्वतः सफल मानी जाती है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

छह दशक बाद गिर के जंगलों में फिर से गूंज रही है 'इंडियन ग्रे हॉर्नबिल' पक्षियों की चहचहाहट : राज्य सरकार के री-इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता

▸▸ 2021 में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को अरावली के जंगलों से लाकर दोबारा गिर के जंगलों में बसाया गया, चरणबद्ध तरीके से कुल 40 पक्षियों को गिर के जंगलों में छोड़ा गया

▸▸ हाल में हुए एक अध्ययन में पता चला कि इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों ने अब गिर के जंगलों को अपना स्थायी बसेरा बना लिया है, घोंसले बना रहे हैं और प्रजनन भी कर रहे हैं

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत में वन्यजीव संरक्षण का एक नया अध्याय शुरू हुआ, लुप्त हो चुके चीता और गोडावण जैसे अनेक पशु-पक्षियों को फिर से जंगलों में छोड़ा जा रहा है

गांधीनगर : गुजरात वन विभाग को गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) पक्षी के संरक्षण को लेकर कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी सफलता मिली है। जिसमें 'जंप-स्टार्ट' तकनीक के जरिए जन्मे गोडावण पक्षी के दूसरे चूजे ने जन्म के बाद नाजुक और अहम माने जाने वाले 40 दिनों तक जीवित रहने के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। इसे एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। इसी समय, गुजरात वन्यजीव संरक्षण की सफलता से जुड़ी एक दूसरी बड़ी खबर आई है।

गुजरात के गिर जंगल से छह दशक पहले विलुप्त हो चुके इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (आईजीएच-भारतीय धूसर धनेश) पक्षी को फिर से यहां बसाने की कोशिशों को सफलता मिली है।

छह दशक पहले गिर के जंगल से विलुप्त हो चुके इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को फिर से वर्ष 2021 में अरावली के जंगलों से लाकर गिर में छोड़ा गया था। राज्य सरकार के इस 'इंडियन ग्रे हॉर्नबिल री-इंट्रोडक्शन' नामक प्रोजेक्ट को सफलता मिली है। क्योंकि, इन पक्षियों ने अब गिर के जंगल को अपना स्थायी बसेरा बना लिया है। इतना ही नहीं, ये यहां घोंसले भी बनाते हैं और प्रजनन भी करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत में वन्यजीव संरक्षण का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। लुप्त हो चुके चीता और गोडावण जैसे अनेक जानवरों और पक्षियों को फिर से जंगलों में छोड़ा जा रहा है और उनकी वैज्ञानिक तरीके से निगरानी करते हुए संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में वन विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम गढ़े जा रहे हैं। विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे चुके गोडावण पक्षी से लेकर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के री-इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मिली सफलता इसकी शानदार मिसाल है। वर्ष 2021 में गिर जंगल में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को फिर से बसाया गया था। इस घटना को पांच वर्ष बीत चुके हैं। अब ये पक्षी अपने नए प्राकृतिक आवास के माहौल में ढल चुके हैं और प्रजनन भी कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट की सफलता को दर्शाता है। 1950 और 1960 के दशक में गिर के जंगल से गायब हो चुके इन पक्षियों को फिर से यहां वापस लाने के प्रोजेक्ट की सफलता एक ऐतिहासिक घटना है।"

गुजरात के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली ने कहा, "गुजरात के वन्यजीव संरक्षण के मॉडल ने दुनिया को बताया है कि कैसे अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाया और सुरक्षित रखा जाए। राज्य सरकार के वन्यजीव संरक्षण के विशेष प्रयासों को मिली सफलता पर पूरे देश को गर्व है।"

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पीयर-रिव्यूड जर्नल 'बड्र्स' में 'रीइंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स इन गिर, इंडिया : इनसाइट्स इन टू रेंजिंग, हैबिटेट यूज, नेस्टिंग एंड बिहेवियरल पैटर्न' शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। इस शोध पत्र में गुजरात वन विभाग और उनसे जुड़ी संस्थाओं के द्वारा गिर में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को वापस लाने के प्रयासों का पहली बार व्यापक आकलन पेश किया गया है।

पारिस्थितिकी तंत्र में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल का अहम योगदान

गुजरात के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने कहा, "इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (आईजीएच) पक्षी को गिर के जंगल में छोड़ने के बाद, पहले वर्ष में एक जोड़े ने सफलतापूर्वक प्रजनन किया, जबकि दूसरे वर्ष में तीन और प्रजनन करने वाले जोड़ों ने घोंसले बनाए। यह दिखाता है कि इन पक्षियों ने गिर को फिर से अपना घर बना लिया है। ये पक्षी वृक्षों के बीज को लंबी दूरी तक फैलाने में माहिर होते हैं। उनका यह व्यवहार पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पक्षी फलदार पेड़ों के बीजों को दूर-दूर तक पहुंचाकर जंगलों के प्राकृतिक पुनर्जीवन में मददगार साबित होते हैं।"

गिर के जंगलों में 40 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल छोड़े गए थे

जूनागढ़ वन सर्कल के वन संरक्षक और इस अध्ययन के सह-लेखक श्री मोहन राम ने कहा, "इस प्रोजेक्ट के तहत दो चरणों में 40 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को गिर के जंगलों में छोड़ा गया। वर्ष 2021 और 2022 के दौरान 28 पक्षी छोड़े गए। इसके बाद वर्ष 2023 में 12 और पक्षी छोड़े गए। छोड़े गए पक्षियों में से 11 नर पक्षियों में सैटेलाइट टांसमीटर लगाए गए, जिससे वैज्ञानिक कई वर्षों तक उनकी गतिविधियों, उनके रहने की जगहों और प्रजनन व्यवहार पर नजर रख सके।"

श्री मोहन राम ने आगे कहा, "गुजरात के अरावली के जंगलों में बसे इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को लाकर गिर में फिर से बसाया गया। गिर के जंगलों का अध्ययन करने पर विशेषज्ञों को महसूस हुआ कि अब गिर में परिस्थितियां इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी के लिए काफी अनुकूल हैं।"

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉ. जयपाल सिंह ने कहा, "ग्रे हॉर्नबिल दशकों पहले गिर से गायब हो गए थे, लेकिन 1965 में गिर वन्यजीव अभयारण्य और 1975 में गिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा में हुए सुधारों ने इस प्रजाति को वापस लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई।"

अब गिर को स्थायी बसेरा बना चुके हैं इंडियन ग्रे हॉर्नबिल

सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चला कि नए छोड़े गए इंडियन ग्रे हॉर्नबिल ने शुरुआत में अनजान माहौल की खोज करते समय व्यापक भ्रमण किया था और उसके बाद वे अपेक्षाकृत छोटे इलाकों में बस गए।

छोड़े जाने के बाद पहले कुछ महीनों के दौरान इन पक्षियों का विचरण क्षेत्र औसतन 61 वर्ग किलोमीटर था। बाद में, इस क्षेत्र से परिचित होने पर यह घटकर लगभग 5.7 वर्ग किलोमीटर रह गया।

इसी प्रकार, शुरुआती खोजबीन के दौरान उनकी औसत दैनिक उड़ान का दायरा 4.3 किलोमीटर था, जो स्थायी होने के बाद घटकर 1.4 किलोमीटर रह गया, जो गिर के इकोसिस्टम के साथ इनके सफल अनुकूलन को दिखाता है।

अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जगन्नाथ मंदिर में नेत्रोत्सव विधि और महाआरती में सहभागी हुए

▸▸ उप मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण करके भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष राज्य के नागरिकों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की

▸▸ ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल की प्रोत्साहक उपस्थिति

गांधीनगर : अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा से पूर्व भगवान का स्वागत और उनका दर्शन करने के लिए भक्तों में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथयात्रा से पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी मंगलवार को जगन्नाथ मंदिर में नेत्रोत्सव विधि में उपस्थित रहे। इस अवसर पर ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल भी मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री के करकमलों से मंदिर में ध्वजारोहण संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के बाद उप मुख्यमंत्री उपस्थित महानुभावों के साथ भगवान की महाआरती में सहभागी हुए। श्री हर्ष संघवी ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया तथा राज्य के नागरिकों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

उल्लेखनीय है कि भगवान 15 दिनों के अनवसर काल के बाद स्वस्थ होकर निज मंदिर पधारते हैं। इस अवसर पर भगवान के तेजस्वी स्वरूप के 'नवयौवन दर्शन' के साथ गर्भगृह में प्रभु की आंखों पर रेशमी पट्टी बांधने की परंपरागत नेत्रोत्सव विधि उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुई। जहां भक्तों को भव्य 'सोनावेश' (शृंगार) में भगवान के दर्शन का लाभ मिला।

अहमदाबाद सहित राज्य के अन्य जिलों में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्राएं करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इस उद्देश्य से गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित अनेक नई पहलों और सोशल पुलिसिंग के जरिए सभी आनुषंगिक तैयारियां सुनिश्चित की हैं।

जमालपुर स्थित जगन्नाथ जी मंदिर में ध्वजारोहण, नेत्रोत्सव विधि और महाआरती में शहर के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, विधायकगण सर्वश्री अमितभाई शाह, कौशिकभाई जैन, दिनेशसिंह कुशवाह, अमूल भट्ट, हसमुखभाई पटेल, उप महापौर श्रीमती अंजूबेन शाह, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणी, पुलिस महानिदेशक श्री जी.एस. मलिक, शहर पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल सहित अहमदाबाद महानगर पालिका के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल, जगन्नाथ मंदिर के महंत श्री दिलीपदास जी महाराज, मंदिर के न्यासीगण और अग्रणियों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे।

आषाढ़ी बीज पर भक्तिमय होगा सूरत, 8 रथ यात्राओं के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच; हाईटेक निगरानी से हर गतिविधि पर रहेगी पुलिस की नजर

सूरत। भगवान श्रीजगन्नाथ की भक्ति, आस्था और परंपरा के पर्व आषाढ़ी बीज पर इस वर्ष सूरत एक बार फिर धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण में सराबोर होगा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाली कुल आठ छोटी-बड़ी रथ यात्राओं और शोभायात्राओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर ली है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, विभिन्न धार्मिक संगठनों की सहभागिता तथा संवेदनशील मार्गों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी नेटवर्क, बॉडी-वॉर्न कैमरे, साइबर मॉनिटरिंग और विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी रथ यात्राएं पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हों।

इसी उद्देश्य से मंगलवार को अश्विनीकुमार पुलिस स्टेशन में एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. करणराज वाघेला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसीपी जोन-1, जोन-2 और जोन-3 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विभिन्न रथ यात्रा समितियों के पदाधिकारियों, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के सदस्यों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों तथा शहर के प्रमुख नागरिकों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बैठक में रथ यात्राओं के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. करणराज वाघेला ने कहा कि रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास रहेगा कि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकें और पूरे आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह बनाए रखी जाए। इसके लिए पुलिस और आयोजकों के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया गया है तथा सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

इस वर्ष वराछा और अश्विनीकुमार पुलिस स्टेशन क्षेत्र से निकलने वाली इस्कॉन मंदिर की लगभग छह किलोमीटर लंबी रथ यात्रा सबसे बड़ा आकर्षण रहेगी। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त महिधरपुरा, उधना और सेक्टर-1 सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल आठ रथ यात्राएं और शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। सभी मार्गों का पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है।

रथ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष रणनीति अपनाई गई है। प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर स्टैटिक ड्यूटी प्वाइंट, मूविंग पेट्रोलिंग, डीप प्वाइंट, ढाबा प्वाइंट तथा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। भीड़ वाले स्थानों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम

(QRT) भी अलर्ट रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं विभिन्न मार्गों पर लगातार निगरानी रखेंगे।

इस बार सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी-वॉर्न कैमरों से लैस किया जाएगा, जिससे प्रत्येक गतिविधि की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। इससे किसी भी विवाद, शिकायत या कानून-व्यवस्था से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच में सहायता मिलेगी। साथ ही पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

शहर में संचालित 'विश्वास प्रोजेक्ट' के अंतर्गत स्थापित हजारों सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे रथ यात्रा मार्ग की निगरानी की जाएगी। इन कैमरों से प्राप्त लाइव फुटेज सीधे पुलिस के हाई-टेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पहुंचेगी, जहां विशेषज्ञ टीम पूरे आयोजन पर लगातार नजर रखेगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित पुलिस टीमों तक पहुंचाई जाएगी।

सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक संदेशों पर रोक लगाने के लिए साइबर क्राइम सेल की विशेष टीम भी सक्रिय रहेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव फैलाने, अफवाह फैलाने या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष योजना तैयार की गई है। जिन मार्गों से रथ यात्राएं गुजरेंगी, वहां आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी तथा वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पहले से ही नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी। एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग कॉरिडोर भी सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में राहत कार्य प्रभावित न हो।

बैठक में विभिन्न रथ यात्रा समितियों के प्रतिनिधियों ने भी पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। आयोजकों ने कहा कि सभी स्वयंसेवकों को अनुशासन बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सहायता और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने का भी निर्णय लिया गया।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे रथ यात्रा के दौरान धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें तथा संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है।

आषाढ़ी बीज पर निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं सूरत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। इस वर्ष व्यापक सुरक्षा प्रबंध, आधुनिक तकनीक और प्रशासन तथा आयोजकों के बेहतर समन्वय के कारण श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में रथ यात्रा का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। पुलिस का विश्वास है कि सभी नागरिकों के सहयोग से यह धार्मिक आयोजन शांति, सद्भाव और उत्साह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न होगा।

रसोई की लाल दाल में छिपा है प्राकृतिक सौंदर्य का राज बिना महंगे कॉस्मेटिक्स के पाएं दमकती त्वचा-शहनाज़ हुसैन

बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लेकर आता है, लेकिन यही मौसम त्वचा के लिए कई तरह की परेशानियां भी खड़ी कर देता है। हवा में बढ़ी नमी, उमस, पसीना, धूल और प्रदूषण के कारण त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक खोने लगती है। किसी की त्वचा रूखी हो जाती है तो किसी को चिपचिपाहट, मुंहासे, दाग-धब्बे और एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, केमिकल युक्त क्रीम और बार-बार ब्यूटी पार्लर का सहारा लेते हैं। इन पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी कई बार मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, बल्कि संवेदनशील त्वचा पर इनके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाते हैं। जबकि प्रकृति ने हमारी रसोई में ही ऐसे कई खजाने छिपा रखे हैं, जो बिना किसी दुष्प्रभाव के त्वचा को स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इन्हीं प्राकृतिक सौंदर्यवर्धक सामग्रियों में लाल मसूर की दाल का विशेष स्थान है।

लाल मसूर की दाल केवल स्वादिष्ट भोजन का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि यह त्वचा की देखभाल के लिए भी एक अत्यंत प्रभावी प्राकृतिक उपाय मानी जाती है। आयुर्वेद और पारंपरिक घरेलू उपचारों में सदियों से मसूर दाल का उपयोग सौंदर्य निखारने के लिए किया जाता रहा है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड तथा अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व त्वचा की गहराई तक पहुंचकर उसे पोषण देते हैं, नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करते हैं और त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से मसूर दाल का फेस पैक लगाने से त्वचा की रंगत में सुधार आता है, मृत कोशिकाएं हटती हैं और चेहरा स्वाभाविक रूप से दमकने लगता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लाल मसूर दाल एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर का काम करती है। इसके महीन कण त्वचा पर जमा गंदगी, अतिरिक्त तेल और मृत कोशिकाओं को हटाकर रोमछिद्रों की सफाई करते हैं। इससे त्वचा खुलकर सांस लेती है और चेहरे पर ताजगी बनी रहती है। यही कारण है कि जिन लोगों की त्वचा बेजान, मुरझाई हुई या असमान रंगत वाली होती है, उनके लिए मसूर दाल का प्रयोग बेहद लाभकारी माना जाता है।

यदि घर पर एक प्रभावी फेस पैक तैयार करना हो तो दो चम्मच लाल मसूर दाल को आधे घंटे के लिए दूध में भिगो दें। जब दाल अच्छी तरह नरम हो जाए तो उसे उसी दूध के साथ पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें। इसमें एक बड़ा चम्मच बेसन, एक चम्मच गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी मिलाकर अच्छी तरह मिश्रित करें। इस पैक को चेहरे, गर्दन और खुले हिस्सों पर समान रूप से लगाएं। लगभग 20 से 25 मिनट बाद जब यह स्वाभाविक रूप से सूखने लगे, तब सामान्य पानी से धो लें। सप्ताह में दो बार इसका उपयोग करने से त्वचा में उल्लेखनीय निखार दिखाई देने लगता है। यदि त्वचा अत्यधिक शुष्क है तो मसूर दाल को रातभर कच्चे दूध में भिगोकर रखें और सुबह उसे बारीक पीस लें। इस पेस्ट में थोड़ा-सा शहद और मलाई मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह मिश्रण त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और उसकी नमी बनाए रखने में मदद करता है। बरसात के मौसम में जब त्वचा बार-बार रूखी और खिंची हुई महसूस होती है, तब यह घरेलू उपाय काफी राहत देता है। तैलीय त्वचा वाले लोगों के लिए भी मसूर दाल किसी वरदान से कम नहीं है। मसूर दाल के पेस्ट में गुलाब जल और कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर लगाने से अतिरिक्त तेल नियंत्रित होता है। इससे मुंहासे कम होने लगते हैं और त्वचा अधिक साफ एवं संतुलित दिखाई देती है। जिन लोगों को बार-बार पिंपल्स की समस्या रहती है, उनके लिए यह पैक विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है।

मसूर दाल के एंटी-बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को संक्रमण से बचाने में भी सहायक होते हैं। यह धूल, धुएं और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करता है। नियमित उपयोग से चेहरे पर मौजूद हल्के दाग-धब्बे, टैनिंग और झाइयों में भी धीरे-धीरे सुधार दिखाई देता है। यही वजह है कि कई प्राकृतिक सौंदर्य उपचारों में मसूर दाल को प्रमुख सामग्री के रूप में शामिल किया जाता है।

त्वचा की मालिश के लिए भी मसूर दाल का उपयोग किया जा सकता है। जब फेस पैक लगभग 70 से 75 प्रतिशत सूख जाए, तब हाथों में थोड़ा गुलाब जल लगाकर हल्के हाथों से गोलाकार गति में चेहरे की मालिश करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, त्वचा में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और चेहरे पर प्राकृतिक गुलाबी आभा दिखाई देने लगती है। इसके बाद ताजे पानी से चेहरा धोकर हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें, जिससे त्वचा लंबे समय तक मुलायम बनी रहे।

संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को किसी भी घरेलू फेस पैक का उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट अवश्य करना चाहिए। यदि त्वचा पर किसी प्रकार की जलन, लालिमा या खुजली महसूस हो तो उसका उपयोग रोक देना चाहिए। इसके अलावा मसूर दाल का फेस पैक सप्ताह में दो या अधिकतम तीन बार ही लगाना उचित माना जाता है। अत्यधिक उपयोग करने से त्वचा रूखी हो सकती है।

सौंदर्य विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी देखभाल के साथ-साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, भरपूर नींद और तनावमुक्त जीवनशैली भी त्वचा की सुंदरता बनाए रखने के लिए उतनी ही आवश्यक है। यदि प्राकृतिक उपचारों को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए तो बिना महंगे कॉस्मेटिक्स और रासायनिक उत्पादों के भी स्वस्थ, कोमल और दमकती त्वचा प्राप्त की जा सकती है।

आज जब बाजार में सौंदर्य उत्पादों की लंबी श्रृंखला मौजूद है, तब भी प्राकृतिक उपायों का महत्व कम नहीं हुआ है। लाल मसूर की साधारण-सी दाल यह साबित करती है कि खूबसूरती केवल महंगे प्रसाधनों से नहीं, बल्कि प्रकृति की सरल और पोषक देन से भी हासिल की जा सकती है। यदि सही तरीके से और नियमित रूप से इसका उपयोग किया जाए तो यह त्वचा को प्राकृतिक चमक देने के साथ-साथ लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि सौंदर्य विशेषज्ञ वर्षों से इस घरेलू नुस्खे को सुरक्षित, किफायती और प्रभावी विकल्प के रूप में अपनाने की सलाह देते रहे हैं।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के विट्ठलपुर प्लांट का डीआरएम वेद प्रकाश ने किया दौरा

रेल मार्ग से दोपहिया वाहनों के परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल; रेलवे अधिकारियों एवं होंडा प्रबंधन के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने 14 जुलाई, 2026 को गुजरात के विट्ठलपुर स्थित होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) के प्लांट का दौरा किया। इस अवसर पर रेलवे अधिकारियों एवं होंडा प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें होंडा के स्कूटर एवं अन्य दोपहिया वाहनों का रेल मार्ग से परिवहन प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि विट्ठलपुर स्थित होंडा प्लांट में प्रतिदिन 7,500 से अधिक स्कूटरों का उत्पादन होता है, जिन्हें वर्तमान में ट्रकों के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। अब भारतीय रेलवे के माध्यम से इन दोपहिया वाहनों का परिवहन शुरू करने की दिशा में दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के दौरान रेल परिवहन के लिए आवश्यक परिचालन व्यवस्था, लोडिंग एवं अनलोडिंग सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स, रेक उपलब्धता तथा विभिन्न समन्वयात्मक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया। रेल आधारित परिवहन शुरू होने से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी, परिवहन लागत में कमी आएगी, समयबद्ध एवं सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

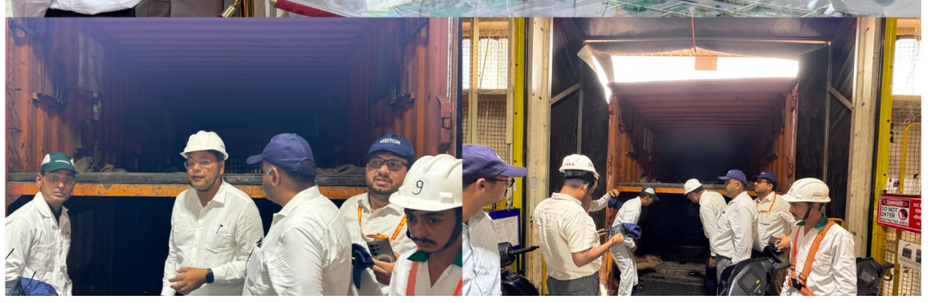

डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने कहा कि भारतीय रेलवे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक एवं विश्वसनीय माल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल रेलवे एवं ऑटोमोबाइल उद्योग के बीच सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगी तथा रेल आधारित लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद अहमदाबाद मंडल के माल परिवहन (फ्रेट) राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही, यह पहल भारतीय रेलवे के "ग्रीन लॉजिस्टिक्स" एवं "मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट" को बढ़ावा देने के उद्देश्य को भी सशक्त करेगी।

अहमदाबाद मंडल क्षेत्र के उद्योगों को रेल नेटवर्क से जोड़ने, माल ढुलाई को अधिक सुरक्षित, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने तथा उद्योगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना से बदली गोधरा की तस्वीर, 7 करोड़ की लागत से बना आधुनिक रेल हब

वडोदरा। भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोधरा रेलवे स्टेशन का व्यापक कायाकल्प पूरा हो गया है। लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस परियोजना ने वर्षों पुराने स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुविधाजनक और यात्री-केंद्रित स्वरूप प्रदान किया है। स्टेशन पर नई अधोसंरचना, विश्वस्तरीय सुविधाओं, बेहतर यातायात प्रबंधन और दिव्यांग-अनुकूल व्यवस्थाओं के साथ अब यात्रियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह पुनर्विकास केवल स्टेशन के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि गोधरा और आसपास के क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक विकास को भी नई गति देगा।

भारतीय रेल देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में गोधरा रेलवे स्टेशन का चयन किया गया, जहां यात्रियों की बढ़ती संख्या, बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापक पुनर्विकास किया गया। इस परियोजना के माध्यम से स्टेशन को आधुनिक वास्तुकला, उन्नत यात्री सुविधाओं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया गया है।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने बताया कि गोधरा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भारतीय रेल की आधुनिक और यात्री-केंद्रित सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। इससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का डिजाइन तैयार किया गया है, ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ने वाले यात्री भार को भी आसानी से संभाला जा सके।

परियोजना के तहत मुख्य स्टेशन भवन का पूरी तरह आधुनिकीकरण किया गया है। लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में आकर्षक और आधुनिक फसाड तैयार किया गया है, जिससे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। इसके साथ ही 120 वर्गमीटर का विशाल पोर्च तथा लगभग 700 वर्गमीटर का अत्याधुनिक कॉन्कोर्स हॉल विकसित किया गया है, जहां यात्रियों को टिकटिंग, प्रतीक्षा और आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। महिलाओं की सुविधा को विशेष प्राथमिकता देते हुए 60 वर्गमीटर का आधुनिक महिला प्रतीक्षालय भी बनाया गया है, जिसमें आरामदायक बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार (सेकेंड एंट्री) का भी विकास किया गया है। इसके अंतर्गत 650 वर्गमीटर क्षेत्र में नया स्टेशन भवन तैयार किया गया है, जबकि 1500 वर्गमीटर का सर्कुलेटिंग एरिया विकसित कर यात्रियों और वाहनों की आवाजाही को अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया है। इससे स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा और प्रवेश एवं निकास दोनों अधिक सुगम बनेंगे।

स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2/3 और 4/5 का भी व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है। लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्र में नई और मजबूत प्लेटफॉर्म सरफेसिंग की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ और उन्नत शौचालय, डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, आधुनिक साइनेज तथा दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए विशेष टैक्टाइल टाइल्स लगाई गई हैं। इन सुविधाओं से स्टेशन पूरी तरह समावेशी और सभी वर्गों के यात्रियों के लिए सुविधाजनक बन गया है।

बरसात और गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए प्लेटफॉर्मों पर 3000 वर्गमीटर क्षेत्र में कवर ओवर प्लेटफॉर्म (COP) का निर्माण किया गया है। अब यात्रियों को धूप, बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी सुरक्षित और आरामदायक प्रतीक्षा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए लाभदायक होगी, जिन्हें ट्रेनों की प्रतीक्षा लंबे समय तक करनी पड़ती है।

स्टेशन परिसर में यातायात व्यवस्था को भी पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। मौजूदा सर्कुलेटिंग एरिया के अतिरिक्त 1500 वर्गमीटर का नया प्रवेश क्षेत्र विकसित किया गया है। साथ ही 2000 वर्गमीटर क्षेत्र में स्कूटर पार्किंग तथा 2000 वर्गमीटर में आधुनिक एप्रोच रोड का निर्माण किया गया है। इससे स्टेशन परिसर में वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो गई है तथा यात्रियों को पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

रेलवे ने दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को भी विशेष महत्व दिया है। स्टेशन पर आधुनिक लिफ्ट स्थापित की गई हैं, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांग यात्रियों और भारी सामान लेकर आने वाले लोगों को प्लेटफॉर्मों तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षालयों का आधुनिकीकरण, अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण, स्टेशन परिसर का आकर्षक सौंदर्यीकरण और स्वच्छता व्यवस्था को भी नए स्तर पर पहुंचाया गया है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गोधरा रेलवे स्टेशन का यह पुनर्विकास केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की स्मार्ट रेल अधोसंरचना का हिस्सा है। आधुनिक डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, सुव्यवस्थित यातायात, स्वच्छ वातावरण और यात्री-अनुकूल सुविधाओं के कारण यह स्टेशन आने वाले वर्षों में पश्चिम रेलवे के प्रमुख आधुनिक स्टेशनों में शामिल होगा।

गोधरा, पंचमहल और आसपास के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों के लिए यह परियोजना विशेष महत्व रखती है। स्टेशन के आधुनिकीकरण से व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्थानीय उद्योगों को भी लाभ मिलने की संभावना है। बेहतर रेल सुविधाओं के कारण क्षेत्र में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

भारतीय रेल का मानना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना केवल स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की रेल अधोसंरचना को भविष्य के अनुरूप विकसित करने का राष्ट्रीय अभियान है। गोधरा रेलवे स्टेशन का यह आधुनिक स्वरूप इसी सोच का परिणाम है, जहां यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और तकनीकी उन्नयन को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में यह स्टेशन न केवल यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक यात्रा का केंद्र बनेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार सिद्ध होगा।

सूरत के गणेशोत्सव में नई परंपरा की शुरुआत, हिंदू मिलन मंदिर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए चुनी धातु की गणेश प्रतिमा

सूरत। पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक परंपराओं के संतुलन की दिशा में सूरत का प्रसिद्ध कतारगाम स्थित हिंदू मिलन मंदिर इस वर्ष गणेशोत्सव में एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। वर्षों से सार्वजनिक गणेशोत्सव में स्थापित की जाने वाली पारंपरिक मिट्टी की प्रतिमा के स्थान पर इस बार पहली बार मेटल (धातु) की भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संस्था का मानना है कि यह पहल केवल एक नई परंपरा की शुरुआत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

हर वर्ष देशभर में लाखों गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान नदियों, तालाबों और समुद्र में बड़ी मात्रा में रंग, प्लास्टर, सजावटी सामग्री और अन्य अवशेष पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मिट्टी की प्रतिमाओं को बढ़ावा दिया गया, लेकिन बड़े सार्वजनिक आयोजनों में प्रतिमा निर्माण, परिवहन, विसर्जन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कई व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने आईं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिंदू मिलन मंदिर ने इस बार स्थायी धातु की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हिंदू मिलन मंदिर के अध्यक्ष पूज्य स्वामी अंबरीशानंदजी महाराज के मार्गदर्शन में लिया गया है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि धार्मिक परंपराओं की मूल भावना को बनाए रखते हुए समय के अनुरूप ऐसे विकल्प अपनाने की आवश्यकता है, जो प्रकृति और समाज दोनों के हित में हों। धातु की प्रतिमा का उपयोग करने से हर वर्ष नई प्रतिमा तैयार कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और श्रद्धालु उसी श्रद्धा एवं विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सकेंगे। संस्था के अनुसार, इस पहल से सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण को मिलेगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जलाशयों में होने वाला प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। इसके अलावा प्रतिमा निर्माण, रंगाई, परिवहन और विसर्जन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च भी घटेगा। हर वर्ष प्रतिमा बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

हिंदू मिलन मंदिर का कहना है कि धातु की प्रतिमा स्थायी होने के कारण प्रत्येक वर्ष केवल उसकी विधिवत पूजा और अलंकरण किया जाएगा। गणेशोत्सव समाप्त होने के बाद पारंपरिक विसर्जन के स्थान पर धार्मिक विधि से प्रतीकात्मक विसर्जन कर प्रतिमा को सुरक्षित रखा जाएगा और अगले वर्ष पुनः स्थापित किया जाएगा। इससे धार्मिक भावनाएं भी अक्षुण्ण रहेंगी और प्रकृति पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ेगा। संस्था ने यह भी बताया कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर में भारी यातायात, सुरक्षा व्यवस्था, जलाशयों पर भीड़ और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि अधिक से अधिक सार्वजनिक मंडल स्थायी प्रतिमाओं को अपनाते हैं, तो इन समस्याओं में भी उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इससे प्रशासन को भी राहत मिलेगी और विसर्जन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बन सकेगी।

पूज्य स्वामी अंबरीशानंदजी महाराज ने इस अवसर पर सूरत सहित पूरे गुजरात के सार्वजनिक गणेशोत्सव आयोजकों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। यदि श्रद्धालु और आयोजन समितियां पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाती हैं, तो यह भगवान गणेश के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी निर्वहन होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में धार्मिक आयोजनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परंपराओं का सम्मान करते हुए यदि आधुनिक और टिकाऊ विकल्प अपनाए जाएं तो धर्म और प्रकृति दोनों की रक्षा संभव है। उन्होंने विश्वास जताया कि हिंदू मिलन मंदिर की यह पहल अन्य गणेशोत्सव मंडलों के लिए भी प्रेरणा बनेगी और आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में संस्थाएं इस दिशा में कदम बढ़ाएंगी।

संस्था ने समाज में जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष संदेश भी जारी किए हैं। "पर्यावरण बचाओ, गणेश उत्सव को पवित्र बनाओ" तथा "मिट्टी नहीं, प्रदूषण नहीं... मेटल की प्रतिमाओं से करें पर्यावरण की रक्षा" जैसे संदेशों के माध्यम से लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जल बचाने से जुड़े विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की योजना है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि सार्वजनिक स्तर पर स्थायी प्रतिमाओं का उपयोग बढ़ता है तो नदियों और जलाशयों में प्रतिमा विसर्जन से होने वाले प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इससे जल की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी, जलीय जीवों का संरक्षण होगा और नगर निकायों पर सफाई का अतिरिक्त बोझ भी कम होगा। सूरत में हिंदू मिलन मंदिर की यह पहल केवल एक धार्मिक आयोजन में बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण की नई सोच का प्रतीक बनकर सामने आई है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में यह मॉडल अन्य शहरों और सार्वजनिक गणेशोत्सव समितियों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है।

ज्ञानवापी विवाद में सुलह की राह बंद, प्री-मध्यस्थता वार्ता विफल; अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

वाराणसी। देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील धार्मिक मामलों में शामिल ज्ञानवापी विवाद में आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश फिलहाल सफल नहीं हो सकी है। सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर आयोजित प्री-सुलह (प्री-मध्यस्थता) वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और हिंदू तथा मुस्लिम—दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अब मध्यस्थता केंद्र की पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई की दिशा तय होगी।

यह बैठक वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में आयोजित की गई थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर से संबंधित विभिन्न मुकदमों के पक्षकार, उनके अधिवक्ता और मध्यस्थता प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। कई घंटे तक चली चर्चा के दौरान दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान निकालने का अवसर दिया गया, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। परिणामस्वरूप यह प्रयास बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया।

सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यह जानना था कि क्या वर्षों से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का समाधान अदालत के बाहर आपसी सहमति से संभव है। इसी उद्देश्य से औपचारिक मध्यस्थता शुरू करने से पहले प्री-सुलह वार्ता आयोजित कर दोनों पक्षों का रुख जानने का प्रयास किया गया था। हालांकि बैठक के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्ष अपने-अपने दावों और कानूनी अधिकारों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

हिंदू पक्ष की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बैठक के बाद कहा कि यह विवाद केवल संपत्ति या प्रशासनिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों और कानूनी अधिकारों के जटिल प्रश्न जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में समझौते की संभावना नहीं बन सकी। उनका कहना था कि अब इस मामले में अंतिम निर्णय और आगे की दिशा सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा।

दूसरी ओर, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने बैठक से पहले ही मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर अपनी असहमति जता दी थी। कमेटी के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन ने कहा कि प्री-मध्यस्थता की प्रक्रिया बाध्यकारी नहीं है और कमेटी अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में ही अपना पक्ष रखेगी। उनका कहना था कि विवाद का समाधान केवल न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में दोनों पक्षों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि यदि आपसी सहमति से कोई रास्ता निकलता है तो लंबे समय से चल रहे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो सकता है। लेकिन किसी भी पक्ष ने अपने मूल दावों में कोई नरमी नहीं दिखाई। हिंदू पक्ष ने अपने धार्मिक अधिकारों और दावों को बरकरार रखने की बात दोहराई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने भी अपने कानूनी और धार्मिक अधिकारों से समझौता करने से इनकार कर दिया।

ज्ञानवापी विवाद पिछले कई वर्षों से न्यायालयों में विचाराधीन है और वर्ष 2022 के बाद से इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान परिसर के सर्वेक्षण, पूजा-अधिकार, संरचनात्मक स्थिति तथा विभिन्न याचिकाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश भी सामने आए हैं। अब प्री-सुलह वार्ता के विफल हो जाने के बाद मामला फिर पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आ गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यस्थता विफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और यह तय करेगा कि मामले की नियमित सुनवाई किस प्रकार आगे बढ़ाई जाए। अदालत यह भी निर्धारित कर सकती है कि लंबित याचिकाओं की सुनवाई किस क्रम में होगी और किन कानूनी प्रश्नों पर पहले निर्णय दिया जाएगा।

ज्ञानवापी विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सतर्क रखी गई है और किसी भी प्रकार की अफवाह या सामाजिक तनाव की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचने की अपील की है।

अब इस बहुचर्चित मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी।

अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने रथयात्रा के पूरे रूट का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

- 16.2 किमी लंबे परंपरागत रथयात्रा रूट पर 3 मुख्य रथों के साथ 18 गजराज, 103 ट्रक और 30 अखाड़े शामिल होंगे
- सुरक्षा की दृष्टि से पूरे रूट को 26 रेंज और 1397 पॉइंट्स में बांटा गया, 10 आईजी और डीआईजी सहित 30,000 से अधिक पुलिस जवान तैनात
- स्मार्ट पुलिसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और 3डी मैपिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का होगा उपयोग
- 100 से अधिक ड्रोन, गजराज पर जीपीएस-सीसीटीवी, संदिग्धों के लिए 'एआई फेस रिकॉग्निशन कैमरे' और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए '3डी मैपिंग और बॉडी वॉर्न कैमरा' जैसे इंतजाम सुनिश्चित किए गए

गांधीनगर : अहमदाबाद शहर में आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि के पावन पर्व पर निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं भव्य रथयात्रा को लेकर नागरिकों में अद्भुत उत्साह और भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है।

राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को रथयात्रा के समग्र रूट का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की व्यापक समीक्षा की ताकि यह ऐतिहासिक रथयात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो।

उप मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस प्रमुख श्री जी.एस. मलिक और शहर पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत सहित उच्च अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री ने रूट के संवेदनशील पॉइंट्स, कानून व्यवस्था की स्थिति और आपातकालीन सेवाओं के अग्रिम आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की।

रथयात्रा रूट के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा 16.2 किलोमीटर के परंपरागत रूट पर भ्रमण करेगी, जिसमें 3 मुख्य रथों के साथ 18 गजराज, 103 ट्रक, 30 अखाड़े और कई भजन मंडलियां शामिल होंगी।

सुरक्षा इंतजामों के बारे में बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रथयात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए पूरे रूट को 26 रेंज, 53 एरिया और 1397 पॉइंट्स में बांटा गया है। समग्र रूप पर 10 आईजी और डीआईजी, 42 डीसीपी और 88 एसीपी अधिकारियों सहित 30,000 से अधिक पुलिस जवानों, 15 एसआरपीएफ और 9 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं।

रथयात्रा में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रथयात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और निगरानी तथा 3डी मैपिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।

उन्होंने बताया कि 100 से अधिक ड्रोन के जरिए लाइव सर्विलांस, हाथियों की देखरेख के लिए जीपीएस, सीसीटीवी और डेसिबल मीटर, बॉडी-वॉर्न कैमरे, हाईटेक वायरलेस सिस्टम, एआई वॉयस बॉट, एंटी-ड्रोन गन और संदिग्ध तत्वों एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए 'एआई फेस रिकॉग्निशन कैमरे' जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस ने पिछले एक महीने के दौरान सभी समाजों के साथ बैठकों और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करके भाईचारे का एक अद्भुत माहौल बनाया है, इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग और सभी नागरिकों को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री ने रूट निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किए और उनका हौसला बढ़ाया।

उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे बिना किसी धक्का-मुक्की के भगवान के दर्शन करें और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूट की जर्जर और खतरनाक इमारतों पर चढ़ने से बचें।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद शहर पुलिस के निष्ठापूर्वक कार्यों और पूर्व तैयारियों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी और मानवबल के उत्कृष्ट तालमेल से यह पर्व पूरी आस्था और उत्साहपूर्ण माहौल में निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा।

रथयात्रा रूट निरीक्षण में अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, विधायक श्री कौशिक जैन, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल और अहमदाबाद महानगर पालिका के कई पदाधिकारी, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणी सहित पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी एवं सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।

न्यायमूर्ति आनंद नारायण मुल्ला की 1961 में पुलिस पर की गई ऐतिहासिक टिप्पणी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज विवादों में घिरी पुलिस को लेकर जनता के मन में एक अलग ही तरह का भय पैदा हो गया है। ठीक 65 साल पहले, 1961 में, एक ऐसे मामले में जहां भारतीय पुलिस ने असंवैधानिक, गैरकानूनी या असभ्य व्यवहार किया था, प्रसिद्ध कवि और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आनंद नारायण मुल्ला ने मोहम्मद नईम बनाम सरकार के मामले में भारतीय पुलिस व्यवस्था पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी थी। जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में पुलिस दमन और कानूनी व्यवहार का विश्लेषण अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, जबकि न्यायमूर्ति आनंद नारायण मुल्ला की ऐतिहासिक चेतावनी आज भी प्रासंगिक है।

इस संदर्भ में, पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश आनंद नारायण मुल्ला लिखते हैं कि "पूरे देश में ऐसा कोई भी गैरकानूनी समूह नहीं है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड उस संगठित बल के करीब भी आता हो जिसे हम भारतीय पुलिस बल कहते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अगर मुझे विश्वास होता कि मैं अपने प्रयासों से पुलिस बल की इस गंदगी को साफ कर सकता हूँ, तो मैं अपना संघर्ष जारी रखने से नहीं डरता।" लेकिन इस आदेश के बाद, न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "अगर मैं अक्सर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये टिप्पणियाँ इतना ध्यान क्यों आकर्षित करती हैं? इससे यह भी पता चलता है कि मेरी टिप्पणियों के आधार पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज, 65 साल बाद, ऐसा लगता है कि भारतीय पुलिस की स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। या यूँ कहें कि समाज और भी अधिक असंवेदनशील हो गया है। एक बयान की बात छोड़िए, पुलिस के व्यवहार के सैकड़ों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं और वायरल हो जाते हैं, फिर भी पुलिस के चरित्र में कोई सुधार दिखाई नहीं देता।"

सूरत में बाढ़ के बाद त्वचा रोगों के मामले बढ़े, 18 चिकित्सा शिविरों में 4 हजार से अधिक लोगों की जांच की गई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के लोग भारी बारिश और बाढ़ की गंभीर स्थिति से अभी उबर ही रहे थे कि सूरत की विभिन्न नदियों में अवैध निर्माणों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सताने लगीं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद, गंदगी, कीचड़ और दूषित पानी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा रोगों के मामलों में काफी वृद्धि हुई है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य शिविरों में अब तक इलाज के लिए आए मरीजों में त्वचा रोग के मरीजों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के बाद, नगरपालिका ने प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, 11 जुलाई से शहर के प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर शुरू किए गए हैं ताकि नागरिकों को अस्पताल जाने की आवश्यकता न पड़े और उन्हें मौके पर ही तत्काल उपचार मिल सके।

इस संबंध में, नगरपालिका ने अथवा जोन में एक, उधना जोन-ए में पांच, वराछा जोन-ए में तीन, सारथाना जोन में दो और लिंबायत जोन में चार सहित कुल 18 स्थानों पर चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों, त्वचा विशेषज्ञों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम नागरिकों की जांच कर रही है और उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा रही है।

11 जुलाई से रविवार दोपहर तक लगभग 4000 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। इनमें से 825 मरीजों का त्वचा रोगों का इलाज किया गया। बाढ़ के बाद स्वास्थ्य के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसके अलावा, 357 लोगों को बुखार, 264 लोगों को साधारण दस्त और 82 लोगों को दस्त-उल्टी की शिकायत थी।

नगरपालिका के अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा स्थिति में त्वचा संक्रमण, बुखार और जलजनित रोगों को ध्यान में रखते हुए निरंतर स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। इस संबंध में शुरू किए गए सभी चिकित्सा शिविर अगले शनिवार तक चालू रहेंगे।